भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

बायोटेक्नोलॉजी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1423

उत्तर देने की तारीख : 31 जुलाई, 2024

चिकित्सा उपकरणों की लागत

1423. श्री नरेश गणपत म्हस्के:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री प्रवीण पटेल:

श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

श्री हरीभाई पटेल:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने चिकित्सा इमेजिंग की उच्च लागत और कम उपलब्धता को देखते हुए इसके वहनीय और विश्वसनीय समाधानों तक पहुंच प्रदान करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ख) 'मेक इन इंडिया-मेड फॉर द वर्ल्ड' की अवधारणा के अनुरूप इस क्षेत्र में उठाए गए कदम और प्रगति क्या है;

(ग) क्या भारत विश्व के शीर्ष पांच स्वास्थ्य सेवा निर्माताओं में से एक बनकर उभरा है;

(घ) क्या चिकित्सा उपकरणों को देश में उभरते क्षेत्रों में से एक माना जाता है; और

(ड.) सरकार द्वारा भारत को अपना विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क), (ख) और (ङ): जी हां। भारत सरकार ने देशभर में किफायती और विश्वसनीय चिकित्सा इमेजिंग समाधान विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। व्यावसायीकृत इमेजिंग प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- 3नेत्र क्लासिक- रेटिना इमेजिंग के लिए डिजिटल नॉन-मायड्रियाटिक फंडस कैमरा- इस उपकरण का उपयोग 2.5+ मिलियन स्क्रीनिंग करने के लिए किया गया है; 28 से अधिक देशों में इसके 2600 से अधिक उपकरण बिक चुके हैं।

- 3नेत्र नियो – इस उपकरण का एक और संस्करण, एक कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल, उन्नत वाइड-फील्ड डिजिटल इमेजिंग सिस्टम है जो नेत्र रोगों की पहचान करने के लिए है, जिसका उपयोग नवजात शिशुओं में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी (आरओपी) की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है और इसे आयातित उपकरण के मूल्य के पांचवें हिस्से पर बेचा गया है। इस उपकरण से 10000 से अधिक स्क्रीनिंग पूरी की गई हैं और 9 देशों में इसके 100 से अधिक उत्पाद बेचे गए हैं।

- स्वदेशी हल्के, कॉम्पैक्ट, उच्च स्तरीय मेग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) स्कैनर

कैंसर स्क्रीनिंग, एंडोस्कोपी आदि के लिए विभिन्न इमेजिंग प्रौद्योगिकियों की प्रतिकृतियां नैदानिक वैधता के चरण में हैं।

'मेक इन इंडिया-मेड फॉर द वर्ल्ड' के साथ तालमेल बिठाने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रहे हैं और इसमें तेजी ला रहे हैं तथा प्रयोगशाला स्तर के प्रोटोटाइप को पैकेज्ड मॉडल में बदलने और व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग करने के लिए शिक्षाविदों, स्टार्ट-अप और संबंधित संगठनों को एक सक्षम मंच प्रदान कर रहे हैं।

इसके अलावा, जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी), जो डीबीटी द्वारा धारा 8 के तहत स्थापित एक गैर-लाभकारी, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, वह किफायती चिकित्सा इमेजिंग समाधानों सहित चिकित्सा उपकरणों के विकास का समर्थन करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप, उद्योगों के साथ-साथ साझेदारी करने वाले शैक्षणिक संगठनों के लिए विभिन्न योजनाएं और मिशन कार्यक्रम प्रदान करता है।

औषध विभाग ने मेक-इन-इंडिया को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरणों में विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- "चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण का संवर्धन" के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 3,420 करोड़ रुपये है और जिसकी अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 से 2027-28 तक है, चयनित कंपनियों को भारत में निर्मित चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर 5% की दर से पांच साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना के तहत शामिल चार लक्षित खंडों में रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (आयनीकरण और गैर-आयनीकरण विकिरण उत्पाद दोनों) और न्यूक्लियर इमेजिंग उपकरण शामिल हैं। इस योजना के तहत, उच्च-स्तरीय

चिकित्सा उपकरणों का घरेलू विनिर्माण शुरू हो गया है, जिसमें लीनियर एक्सेलेरेटर, एमआरआई स्कैन, सीटी-स्कैन, मैमोग्राम, सी-आर्म, एमआरआई कॉइल आदि शामिल हैं।

- 400 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय वाली "चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन" योजना में आगामी चिकित्सा उपकरण पार्कों में सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए चयनित 4 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, प्रत्येक राज्य को 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए अंतिम अनुमोदन दे दिया गया है।
- सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण समूहों को सहायता तथा चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण की योजना भी शुरू की गई है, जिसका वित्तीय परिव्यय तीन वर्ष की अवधि के लिए 300 करोड़ रुपये है, ताकि चिकित्सा उपकरण समूहों में 12 सामान्य अवसंरचना सुविधाओं को सहायता प्रदान की जा सके तथा 12 परीक्षण सुविधाएं स्थापित की जा सकें।

(ग) और (घ): जी हाँ। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को देश में उभरते क्षेत्रों में से एक माना गया है। भारत वैश्विक चिकित्सा उपकरण उद्योग में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशियाई चिकित्सा उपकरण बाजार में चौथा सबसे बड़ा बाजार है और विश्व के शीर्ष 20 वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजारों में से एक है।

****